माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र चौहान के समक्ष

रघुबीर सिंह
-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य
-प्रतिवादी

2009 का सी.आर.एल. आर. 664
21 अक्टूबर, 2010

पंजाब गन्ना (खरीद और आपूर्ति का विनियमन) नियम, 1958-भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा 420-गन्ने का वजन कम पाया गया-तौल पुल के मालिक और एक कर्मचारी के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर-याचिकाकर्ता केवल तौल पुल पर गन्ना तौलने के लिए कार्यरत है- तौल पुल का एकमात्र लाभार्थी इसका मालिक है, एक सह-अभियुक्त पहले ही बरी हो चुका है- याचिकाकर्ता का गन्ना उत्पादकों को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था - आईपीसी की धारा 420 के घटक याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनाए गए - याचिका की अनुमति दी गई, निचली अदालतों द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी करने का आदेश दिया गया।

यह निर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा ,पुल का मालिक नहीं होने के कारण ,उसका वजन कम करने का कोई मकसद या इरादा नहीं है क्योंकि वह लेनदेन में लाभार्थी नहीं था। गन्ना क्रय केन्द्र अभियुक्त करनजीत सिंह के प्रभावी नियंत्रण में तथा चीनी मिल के प्रतिनिधि की देखरेख में था। भारतीय दंड संहिता(संक्षेप में 'आई पी सी') की धारा 420 के प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता है। तौल नियमावली 1958 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी।शिकायतकर्ता सतबीर सिंह ने स्वीकार किया है कि गन्ना केंद्र पर नियमावली 1958 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तौल नहीं पाई गई। इसलिए, इन परिस्थितियों में, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मौजूदा मामले में इस तरह का महत्व पूर्ण प्रमाण नहीं है और यह अभियोजन के मामले की सत्यता पर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा, सह-अभियुक्त करनजीत सिंह, तौल ब्रिज का मालिक, जो मुख्य लाभार्थी है, पहले ही विद्वान अपीलीय अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है।

(पैरा18 एवं 20)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, कपिल अग्रवाल।

श्रीमती नवीन मलिक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

जीतेन्द्र चौहान, जे.

1. यह पुनरीक्षण याचिका विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगाधरी द्वारा पारित 3 मार्च, 2004 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा 27 जुलाई, 2000 को पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को बरकरार रखा गया था और उसे दोषी ठहराया गया था व भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध करने के लिए तीन साल की कठोर कारावास की सजा और 1000/- रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनायी गयी थी। 1,000 रुपये जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा की पुष्टि की गई।
2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 फरवरी 1991 को श्री सतबीर सिंह, कृषि विकास अधिकारी (गन्ना), यमुनानगर ने गन्ना उत्पादक सहकारी समिति, रादौर के सचिव की शिकायत पर गन्ना खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रबंधित दो बैलगाड़ियों के गन्ने के वजन में क्रमशः 80 किलोग्राम और 85 किलोग्राम की कमी पाई गई। इसके अलावा वास्तविक वजन से कम वजन दिखाने के लिए वेइंग ब्रिज को भी तार के सहारे एडजस्ट किया हुआ पाया गया। इसी उद्देश्य से तौल पुल के लकड़ी के बक्से में एक छेद भी किया गया था।
3. इस शिकायत पर याचिकाकर्ता-अभियुक्त और उसके सह-अभियुक्त करणजीत सिंह, पुत्र जगजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी एएसआई रणधीर सिंह ने रफ साइट प्लान तैयार किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
4. जांच पूरी होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।
5. अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।
6. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों से पूछताछ की।
7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें दोनों अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया।
8. रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को देखने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने 27 जुलाई, 2000 के फैसले/आदेश द्वारा दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया, जिसे अपील में चुनौती दी गई थी। अपील में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

जगाधरी ने सह-अभियुक्त करनजीत सिंह, वेटिंग ब्रिज के मालिक को बरी कर दिया और वर्तमान याचिकाकर्ता-आरोपी की अपील को खारिज कर दिया, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता किसानों द्वारा लाए गए तौल कांटे पर गन्ना तौलने के लिए सह-अभियुक्त करणजीत सिंह के रोजगार में था। इस तौल पुल का एकमात्र लाभार्थी सह-अभियुक्त करणजीत सिंह था। सह-अभियुक्त करणजीत सिंह को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पहले ही बरी कर दिया गया है। लेन-देन में लाभार्थी नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता का गन्ना उत्पादकों को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का मामला नहीं बनता है।

10. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि मानक के अनुसार, प्रत्येक घंटे के बाद वेट ब्रिज की जांच की जाती है। इस संबंध में केंद्र पर बैलेंस बुक भी रखी जाती है और चीनी मिल के एजेंट भी नियमित अंतराल पर वजन मशीन का निरीक्षण और जांच करते हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो व्यक्तियों, भाल सिंह और बुध राम के स्वामित्व वाली दो बैलगाड़ियों में गन्ने का कम वजन पाया गया, लेकिन, अभियोजन पक्ष द्वारा उन दोनों की जांच नहीं की गई जो अभियोजन पक्ष के संस्करण को संदिग्ध बनाता है।

11. कश्मीर सिंह, पीडब्लू1, और जसपाल सिंह, पीडब्लू2 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता निरीक्षण के समय मौके पर मौजूद नहीं था। क्लच तार के अलावा, जिसका उपयोग वजन निर्धारित करने के लिए किया जा रहा था, लकड़ी का एक टुकड़ा भी केस प्रॉपर्टी के हिस्से के रूप में कब्जे में ले लिया गया क्योंकि इसका उपयोग मशीन में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा था। हालाँकि, उक्त केस संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, मामले की जांच करने वाले रणधीर सिंह और धनपाल सिंह से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई, जिससे आरोपी तत्काल मामले में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन गवाहों से जिरह करने से वंचित हो गए और इस तरह, इसका लाभ याचिकाकर्ता-अभियुक्त को मिलना चाहिए।

12. मकसद स्थापित नहीं है। संपूर्ण भुगतान सह-अभियुक्त करणजीत सिंह को किया गया था और याचिकाकर्ता को कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था और भले ही तर्कों के लिए यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता ने भुगतान स्वीकार कर लिया है, अंततः ऐसे भुगतान का लाभार्थी सह-अभियुक्त करणजीत सिंह ही है,जिसे बाद में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बरी कर दिया है।

13. याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र सबूत शिकायतकर्ता, पीडब्लू4 का बयान है। दोषसिद्धि PW4 के अकेले बयान पर आधारित नहीं हो सकती क्योंकि किया गया वजन पंजाब गन्ना (खरीद और आपूर्ति का विनियमन) नियम, 1958 (इसके बाद "नियम 1958" के रूप में संदर्भित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं था।

14. अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 के अनुसार, यदि कोई अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत विचारणीय है और भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अन्य विशेष क़ानून के साथ दंडनीय है ऐसी स्थिति में विशेष क़ानून के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया और सज़ा प्रबल होगी।

15. विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता नियम 1958 के तहत किसी अपराध के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

16. विद्वान राज्य वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता-आरोपी सह-अभियुक्त का कर्मचारी होने के कारण अपने दायित्व से बच नहीं सकता है।

17. मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

18. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता सह-अभियुक्त करणजीत सिंह के रोजगार में नहीं था। याचिकाकर्ता को किसानों द्वारा तौल कांटे पर लाए गए गन्ने को तौलने के लिए नियुक्त किया गया था। पीडब्लू1 के बयान में आया है कि याचिकाकर्ता कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के निरीक्षण के समय मौके पर मौजूद नहीं था। PW1 के बयान के अलावा, मौजूदा मामले में केस संपत्ति को कभी भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा पुल का मालिक नहीं होने के कारण कम वजन करने का कोई मकसद या इरादा नहीं लगता है क्योंकि वह लेनदेन में लाभार्थी नहीं था। गन्ना क्रय केन्द्र ,अभियुक्त करनजीत सिंह के प्रभावी नियंत्रण में तथा चीनी मिल के प्रतिनिधि की देखरेख में था।

19. भारतीय दंड संहिता की धारा 420 इस प्रकार है: "**420. धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना।** जो कोई धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से धोखेबाज व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को संपत्ति देने, या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने, या किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर करने या सील करने के लिए प्रेरित करता है, और जो परिवर्तित होने में सक्षम है एक मूल्यवान सुरक्षा, किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

कपटपूर्ण कार्यों और संपत्ति के निपटान के बारे में।"

20. उपरोक्त को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता है। वजन नियम 1958 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता सतबीर सिंह, पीडब्लू4, ने स्वीकार किया है कि नियम 1958 द्वारा निर्धारित वजन गन्ना केंद्र पर नहीं पाया गया। इसलिए, इन परिस्थितियों में, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मौजूदा मामले में इस तरह का महत्व पूर्ण प्रमाण नहीं है और यह अभियोजन के मामले की सत्यता पर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा, सह-अभियुक्त करनजीत सिंह, वेट ब्रिज का मालिक, जो मुख्य लाभार्थी है, पहले ही विद्वान अपीलीय अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है।

21. इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में और नियम 1958 में निर्धारित प्रक्रिया के मद्देनजर, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है और निचली अदालतों द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता को उसके ख़िलाफ़ लगे आरोप से बरी कर दिया जाता है।[1]

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा

[1] आर.एन.आर